Note to Foreign Universities regarding Barbarities Committed on Intellectuals of Bangla Desh

5908. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have sent any note to different Universities of the World for drawing their attention to the barbarities committed on intellectuals of Bangla Desh ; and

(b) if not, whether any such step is proposed to be undertaken by Government ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). Indian thinkers and writers have already circulated their "Appeal to the Conscience of the World on the Agony of Bangla Desh" to the universities of the world drawing their attention to the barbarities committed on the intellectuals in East Bengal. In view of this Government do not propose to send a note to universities of the world.

विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

5909. डा० लक्ष्मी नारायण पांडे : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जून को रतलाम में हुई अपनी प्रेस कान्फ्रेन्स में उन्होंने यह कहा था कि सरकार का प्रस्ताव निकट भविष्य में विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). यह बताया गया था कि सरकार विदेशी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार करेगी । यद्यपि विदेशी तेल कम्पनियों की परिष्करणशालाओं तथा अन्य संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी, परिष्करणशालाओं के समझौतों का पुनरीक्षण करने के लिए अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ वर्तमान स्थिति की सरकार विस्तृत रूप में जांच कर रही है ।

बिहार में आवास योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि

5910. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य को आवास योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि दी गई ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आइ० के० गुजराल) : निर्माण और आवास मन्त्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1968-69 तक बिहार सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 958.93 लाख रुपये की राशि ली थी । चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से, अर्थात 1969-70 के वर्ष से, राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए (आवास सहित) सब मिलाकर खंड ऋणों और खंड अनुदानों के रूप में दी जाती है । अतः 1969-70 के वर्ष से राज्य सरकारों द्वारा (बिहार सहित) आवास योजनाओं के लिये प्रयुक्त की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि उपलब्ध नहीं है ।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार को सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1970-71 के वर्ष के अन्त तक, इस मन्त्रालय के माध्यम से, भारत के जीवन बीमा निगम ने कुल 707.02 लाख रुपये के ऋण भी दिये हैं ।

Black Marketing in Blood in Delhi

5911. SHRI BALATHANDAYUTHAM :